IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राजस्थान में प्रादेशिक औधोगिक विषमता के कारक

सुरेन्द्र सिंह[1]
(शोधार्थी, भूगोल विभाग)
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविधालय, उदयपुर

डॉ. विजय सिंह मीना[2]
(सहायक आचार्य, भूगोल विभाग)
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविधालय, उदयपुर

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोधपत्र राजस्थान की प्रादेशिक औधोगिक विषमता को प्रभावित करने वाले कारणों और औधोगिक विषमता की वजह से पड़ने वाले प्रभावों की जाँच करता हैं वस्तुतः औधोगिक इकाइयों के स्थानीयकरण के मुख्य कारकों यथा कच्चे माल, परिवहन, आधारभूत सुविधाएँ, उर्जा आदि कारकों के अलावा भी उधोगों का स्थानीयकरण प्रभावित होता हैं। विस्तृत शोध साहित्य की समीक्षा करने पर कुछ अन्य कारक भी सामने आये हैं जिनमें ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के साथ राजनितिक, सामाजिक, एवं वित्तीय कारकों की महती भूमिका हैं।

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को आधार मानकर विभिन्न औधोगिक संकेतकों के आधार पर प्रादेशिक औधोगिक विषमता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया कि औधोगिक रूप से सर्वाधिक विकसित प्रदेश अरावली प्रदेश तथा न्यूनतम औधोगिक विकास पश्चिमी शुष्क प्रदेश में पाया गया हैं। प्रादेशिक औधोगिक विषमता का प्रभाव न केवल उधोगों तक सिमित रहता हैं बल्कि इनके व्यापक प्रभाव प्रादेशिक विकास, पर्यावरण एवं सामजिक ढांचे में असंतुलन उत्पन्न करते हैं अतः हम कह सकते है कि सतत विकास हेतु सतत औधोगिक विकास को ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक हैं।

***Index Terms* - , प्रदेश, औधोगिक विषमता, सतत औधोगिक विकास,**

परिचय

''प्रदेश '' शब्द का उपयोग प्रशासनिक इकाइयों से बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निरूपित करने के लिए भी किया जाता है और ऐसे क्षेत्र आमतौर पर ऐसे मामलों में जिलों का एक समूह होता हैं। इस मामले में एक '' प्रदेश '' राजस्थान के जिलों के समूह को निरूपित करता हैं जो भौगोलिक रूप से आबद्ध हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में प्रादेशिक औधोगिक विषमता की चर्चा की गयी हैं, यहाँ "प्रादेशिक औधोगिक विषमता" से तात्पर्य हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में उपलब्ध औधोगिक इकाइयों की संख्या में प्रादेशिक स्तर पर पाई जाने वाली विषमता से हैं। राजस्थान को प्रादेशिक स्तर पर पाँच भागों– अरावली पर्वतीय प्रदेश, पश्चिम शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मैदान, पूर्वी मैदान, एवं दक्षिण पूर्वी पठार में विभाजित किया गया हैं। (जोशी 2018, देपन 2011, कुमार 2014)

हेविट और अन्य ने औद्योगीकरण को तीन तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है– पहला, सभी भौतिक वस्तुओं का उत्पादन जिन्हें सीधे भूमि पर नहीं उगाया जाता है, या दूसरा, औद्योगीकरण के रूप में आर्थिक क्षेत्र में जिसमें खनन, विनिर्माण और ऊर्जा शामिल किया हैं। तीसरी परिभाषा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो उद्योग को उत्पादन को आयोजन के एक विशेष तरीका के रूप में देखता है और मानता है कि औद्योगीकरण तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन की एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार माल की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए समाज की क्षमता को बढ़ाता है। (Hewitt et al. 1992)

उद्योग – औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (जे) के अनुसार ''उद्योग'' का अर्थ है कि एक नियोक्ता और उसके श्रमिकों के बीच सहयोग द्वारा की जाने वाली कोई भी व्यवस्थित गतिविधि (चाहे ऐसे श्रमिकों को ऐसे नियोक्ता द्वारा सीधे या किसी भी एजेंसी के माध्यम से नियोजित किया जाता है, जिसमें एक ठेकेदार भी शामिल है) जो मानव इच्छाओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण से संबंधित हैं।

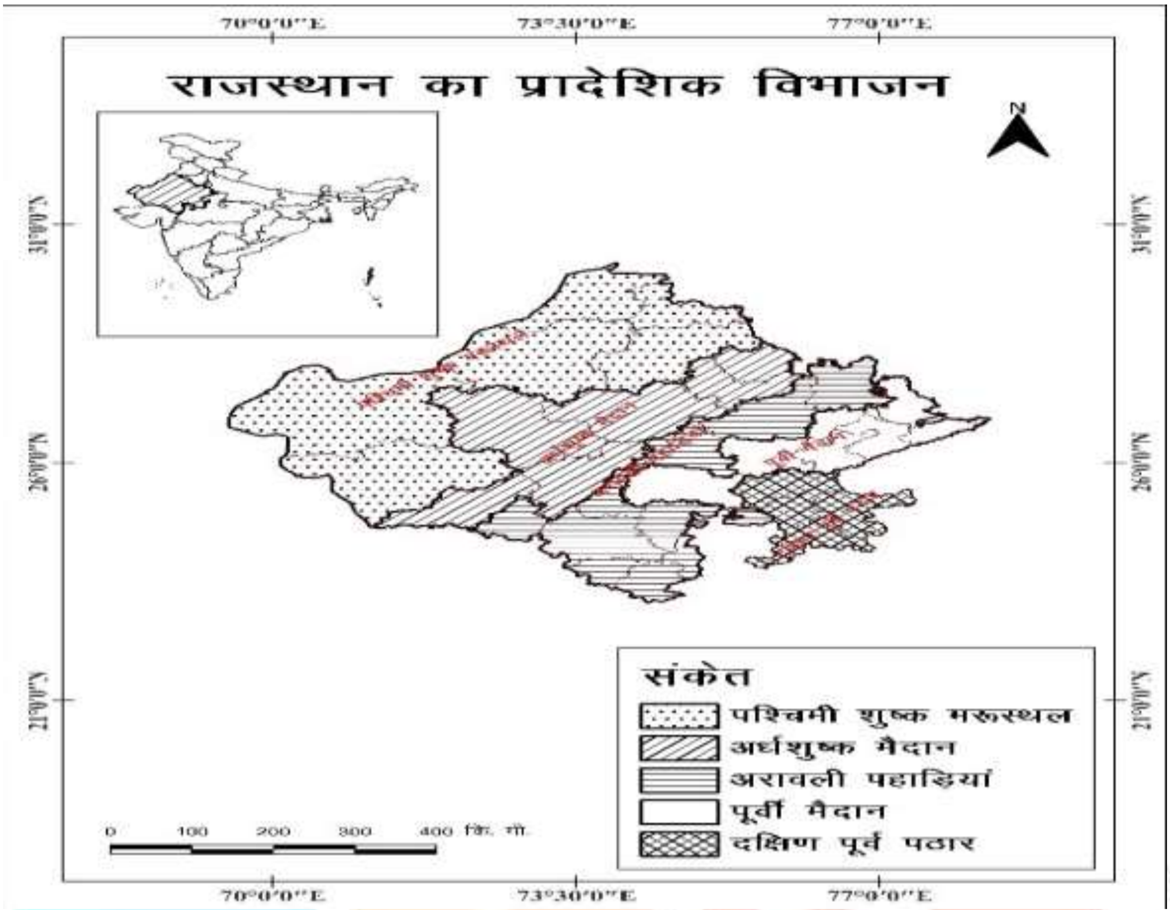

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों पर राष्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन.एस.एस) के 73वें दौर के सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर राजस्थान में कुल 26.87 लाख एम.एस.एम.ई. इकाइयों हैं जो देश की कुल इकाइयों की 4% हैं। यह क्षेत्र राजस्थान में 46.33 लाख रोजगार प्रदान करता है जिनमे 38.31 लाख पुरुष तथा 8.01 लाख महिलाएं रोजगार प्राप्त करती हैं।

राजस्थान में वृहद तथा मध्यम आकार के क्रमशः 452 तथा 235 उद्यम स्थापित हैं, जो क्रमशः 2,21,573 तथा 19,471 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अथार्त इनका कुल औद्योगिक रोजगार में योगदान 4.94% है वहीं एमएसएमई क्षेत्र 95.05% औद्योगिक रोजगार प्रदान करता हैं। अतः सरकार द्वारा तीव्र एवं समावेशी वृद्धि के साथ क्षेत्रीय विषमता को कम करने हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उधम प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं। जैसे– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ,औधोगिक प्रोत्साहन शिविर , स्टैंड अप इण्डिया प्रोग्राम ,राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, राजस्थान औधोगिक विकास नीति 2019, इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम इत्यादि, इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं औधोगिक विकास हेतु खादी एवं ग्रामोधोग आयोग प्रयासरत् हैं ।

अध्ययन क्षेत्र

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है, जो कि उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342239 वर्ग कि.मी. है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% हैं। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार 23°03′–30°12′ उत्तरी अक्षांश तथा 69°30′–78°17′ पूर्वी देशांतर हैं।

इसकी उत्तर व उत्तर पूर्वी सीमाएं पंजाब व हरियाणा से पूर्वी व दक्षिण पूर्वी सीमांए उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश से दक्षिण–पश्चिम सीमा गुजरात से एवं पश्चिम तथा उत्तर–पश्चिम सीमा पाकिस्तान से जुडी हुई हैं। भारत की कुल जनसंख्या (2011 का 5.66%) जनसंख्या राज्य में निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को पांच भागों में बांटा गया हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 7 संभाग एवं 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इस शोध पत्र में औधौगिक विकास के स्तर के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया हैं।

सारणी 1: राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन

1	पश्चिमी शुष्क मरुस्थल	जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमागढ, चुरू
2	अर्धशुष्क मैदान	जोधपुर, जालौर, झुंझुनू, नागौर, पाली, सीकर
3	अरावली पहाड़ियां	अलवर, जयपुर, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चितौडगढ़
4	पूर्वी मैदान	भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाडा, दौसा
5	दक्षिण पूर्व पठार	कोटा, बूंदी, बांरा, झालावाड

स्त्रोत : जोशी (2008), देपन (2011), कुमार (2014)

औधोगिक विषमता

विभिन्न औधोगिक संकेतकों के संयुक्त सूचकांक के आधार पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि राज्य के लगभग 50 प्रतिशत भू भाग वाला अरावली पर्वतीय प्रदेश का औधोगिक विकास के संयुक्त सूचकांक (C.I.) 49.86 प्रतिशत हैं वहीँ पश्चिम शुष्क मरुस्थल (37.91%), अर्धशुष्क मैदान (22.20%), पूर्वी मैदान (8.29%), एवं दक्षिण पूर्वी पठार (7.08%) का औधोगिक विकास के संयुक्त सूचकांक का मान क्रमशः 15.04%, 19.48%, 7.02% एवं 8.60% हैं ।

सारणी 2 :- संयुक्त सूचकांक के आधार पर औधोगिक विषमता

REGION	AREA (%)	POPULATION (%)	TOTAL C.I.	C.I (%)
arawali	24.49	38.15	3.48	49.86
hadauti	7.08	8.30	0.60	8.60
estern plain	8.29	14.01	0.49	7.02
semi arid	22.20	22.86	1.36	19.48
arid	37.91	16.66	1.05	15.04

स्त्रोत : लेखक द्वारा निर्मित

चार्ट 1 : प्रादेशिक औधोगिक विषमता

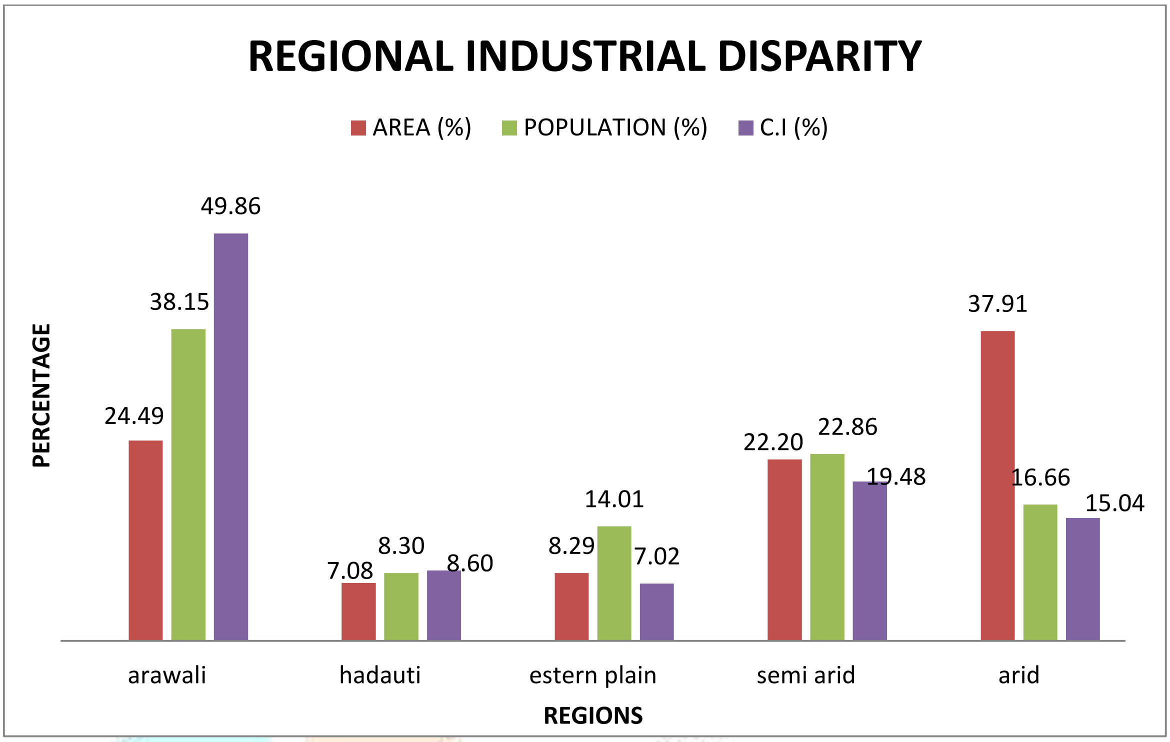

स्त्रोत : लेखक द्वारा निर्मित

सारणी 3 :- MSME उद्योग आधार पंजीयन

	पंजीकृत औधोगिक इकाइयाँ				
प्रदेश	2018	2019	2020	2021	TOTAL
अरावली	46388	50431	66384	13229	176432
पूर्वी मैदान	8149	8458	12226	2061	30894
हाड़ौती पठार	8366	7939	11270	2138	29713
अर्धशुष्क	20887	23441	34983	6943	86254
शुष्क	18725	14315	21609	4814	59463

स्त्रोत : उद्योग आधार पंजीयन

MSME उधोग आधार पंजीयन के आधार पर कुल पंजीकृत इकाइयों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन करके विश्लेषण करने पर पाया गया कि सर्वाधिक पंजीकृत औधोगिक इकाइयों की संख्या अरावली क्षेत्र में है जबकि सबसे कम हाडौती के पठार में हैं। 2018 से 2021 तक अलग अलग वर्षों में भी उधोगों के पंजीकरण का प्रतिरूप समान ही रहा, जिसमे सर्वाधिक से कम पंजीकरण क्रमशः अरावली क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र पूर्वी मैदान तथा हाडौती के पठार में हैं।

चार्ट 2 : पंजीकृत औधोगिक इकाइयाँ :

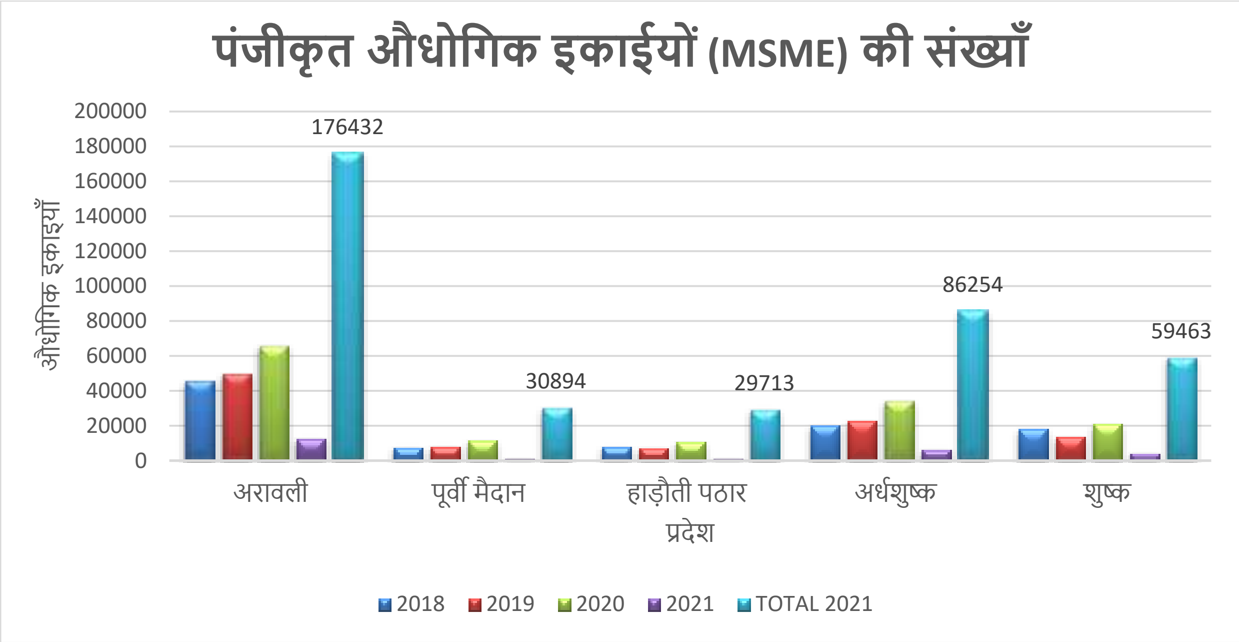

स्त्रोत : लेखक द्वारा निर्मित

पंजीकृत औधोगिक इकाइयों को उनके आकर के आधार पर MSME मध्यम एवं वृहद में विभाजित किया गया, इस वर्गीकरण में भी समान प्रतिरूप देखने को मिला हैं, जिसे नीचे दिए गए पाई चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता हैं।

चार्ट 3 : MSME मध्यम एवं वृहद औधोगिक इकाइयाँ

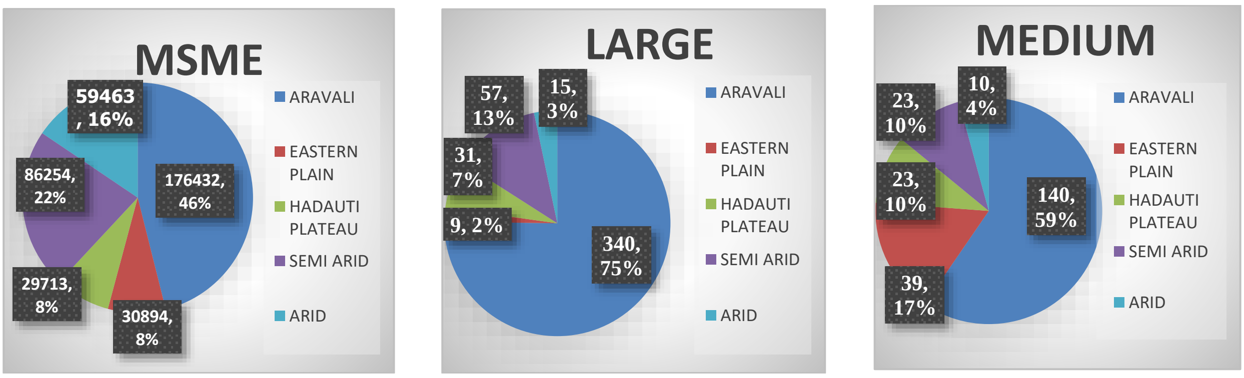

स्त्रोत : लेखक द्वारा निर्मित

उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक

स्थान का चुनाव फर्मों की रणनीतियों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वे कुशल एवं योग्य श्रम, एक संभावित बाजार, अच्छी पहुंच के साथ बुनियादी ढांचे और सरकारी तंत्र एवं योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश करते हैं: वास्तव में "इष्टतम" स्थान की खोज उनके उद्योग को लाभप्रद बनाने में सहायक होता हैं, स्थान एक या अधिक कारकों से प्रभावित होता है जिनका योगदान और विविधता एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बहुत भिन्न हो सकते है और एक ही कारक अलग–अलग प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, एक एकल कारक किसी फर्म के स्थान की व्याख्या नहीं कर सकता है

स्थान सिद्धांत (Location theory) उन सवालों को संबोधित करता है कि कौन सी आर्थिक गतिविधियां कहां और क्यों स्थित हैं। स्थान सिद्धांत या सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत आम तौर पर मानता है कि एजेंट अपने स्वयं के स्वार्थ में कार्य करते हैं। फर्म इस प्रकार उन स्थानों का चयन करती हैं जो उनके मुनाफे को अधिकतम करते हैं और व्यक्ति उन स्थानों का चयन करते हैं जो उनकी उपयोगिता को अधिकतम करते हैं (वेबर, 1985)।

जोर्ज टी. रेनर ने उद्योगों की स्थिति के संबंध में "औधोगिक स्थिति का सामान्य सिद्धांत" दिया जिसके अनुसार किसी उद्योग की स्थापना में छः कारकों (कच्चा माल, उर्जा, बाजार, पूंजी, यातायात एवं श्रम) का योगदान होता हैं, पर अलग अलग उद्योगों में कोई कारक विशेष महत्व रख सकता हैं। चूँकि उद्यमी एक आर्थिक मानव की तरह व्यवहार करता है और उसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है अतः उद्योगों की स्थापना करते समय उद्यमी उपर्युक्त छः कारकों को इस तरह प्रयोग करता हैं कि उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो ताकि अपने लाभ को अधिकतम कर सके। किन्तु उद्यमी के लाभ एवं सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर भी उद्योगों की स्थापना की जा सकती हैं। नवीन एवं तीव्र गति के यातायात साधनों एवं विभिन्न परिवहन मार्गो के विकास से कच्चा माल को ओधोगिक इकाइयों तथा निर्मित माल को बाजारों तक पहुचाना अपेक्षाकृत आसान हो गया हैं।

राजस्थान में प्रादेशिक औधोगिक विषमता के कारक

उधोगों की प्रादेशिक विषमता के पीछे ऐतिहासिक, राजनितिक, भौगोलिक, अवसंरचनात्मक, एवं आर्थिक कारक हैं। राजस्थान में स्वतन्त्रता पूर्व कुटीर उधोगों की
पर निर्भर है। सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, हथकरघा, तिलहन फसल प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योग राजस्थान के अग्रणी उद्योग है। वर्तमान दौर में विशेषतः 1991 के बाद सेवा क्षेत्र में पर्यटन उद्योग ने अपनी विशेष पहचान स्थापित की है। पिछले दशकों में किए गए नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप औधोगिक घरानों ने उद्योगों की स्थापना में अधिकतम लाभ को जबकि राज्य प्रायोजित ओधोगिकरण ने संतुलित प्रादेशिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की हैं फिर भी राष्ट्रिय एवं राज्य स्तर पर ओधोगिक विषमता दिखाई देती हैं स्थापना एवं विकास तथा नगरीय सुविधायें तत्कालीन रियासतों के राजधानी नगरों में थी, जिनका प्रभाव स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तरोत्तर औधोगिक विकास पर भी पड़ा हैं, ऐसे नगरों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर अजमेर आदि जिलें आते हैं।
उद्योगों की स्थापना हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल होता हैं जो स्थान विशेष पर उपलब्धता एवं उसके गुण (शुद्ध, मिश्रित, स्थानापन्न, नष्टता आदि) पर निर्भर करता हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि और पारंपरिक उद्योगों पर आधारित है जो कि चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, क्ले, कपास, ऊन तथा कृषि आधारित कच्चे माल जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों के भंडार पाये जाते हैं किन्तु 57 प्रकार के खनिजों का विदोहन ही किया जाता हैं। राज्य के कुल निर्यात में खनिज आधारित वस्तुओं के निर्यात में संगमरमर, संगमरमर कलाकृतियाँ, ग्रेनाइट एवं अन्य पत्थर (7.73%), धातु (10.01%) तथा रसायन एवं सम्बद्ध (9.51%) हैं जो की कुल निर्यात का 27.25% हैं जो यह सिद्ध करता हैं की राजस्थान में उद्योगों की स्थापना में कच्चे माल का महत्व अधिक हैं। चूँकि अरावली प्रदेश खनिजों की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र हैं इसलिए इस प्रदेश में सर्वाधिक कच्चे माल पर आधारित इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं।

सारणी 4 :- □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□

production of major and minor minerals in 2019-2020 (000 tonne)			
Region	major minerals	minor minerals	total
Aravali Hills Region	48338809.24	97484647.74	145823457
Eastern Plain	0	43022643.08	43022643.08
Hadauti Plateau	3671671.96	18593539.63	22265211.59
Semi Arid Plain	2599364.16	75313829.29	77913193.45
Western Arid desert	10690646.73	33953243.56	44643890.29

Source : https://saar.raj.nic.in

1. यातायात

कच्चे माल के बाद यातायात उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि कच्चे माल को ओधोगिक ईकाइयों तथा तैयार माल को बाजारों तक पहुँचाने के लिए सस्ते, सुरक्षित एवं तीव्र यातायात के साधनों को जरुरत होती हैं। एक उद्योगपति लाभ को अधिकतम करने के प्रयास करता है अतः वह परिवहन व्यय को न्यूनतम रखने का प्रयास करता हैं। हूवर (1948) ने परिवहन लागत की संरचना, परिवहन के साधन एवं दूरी तथा परिवहन के प्रकार के आधार पर परिवहन व्यय का निर्धारण करते हुए औधोगिक इकाई की अवस्थिति का निर्धारण किया।

सारणी 5 :– सड़क तंत्र की लम्बाई

District wise Road Length in Rajasthan till 31.03.2020 (Length in k.m.)								
Region	National Highway	State Highways	Main District Roads	Other District Roads	Village Roads	Total	Area sq. km.	Road density
Aravali	3323	4226	2681	2979	43595	56805	116052	48.95
Eastern Plain	951	1487	1614	1977	12810	18838	31909	59.04
Hadauti Plateau	816	1641	1058	1019	8504	13037	36410	35.81
Semi Arid	2310	4747	2054	5291	28649	43051	55915	76.99
Arid	3218	3023	787	4749	28616	40393	106946	37.77

Source : https://saar.raj.nic.in

राजस्थान में प्रादेशिक स्तर पर परिवहन के साधनों एवं प्रकार में भिन्नता मिलती हैं। राजस्थान में सड़क एवं रेल परिवहन कच्चे माल एवं निर्मित माल के परिवहन हेतु मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, किन्तु जल्दी खराब होने वाली तथा हल्की एवं महँगी वस्तुओं हेतु वायु परिवहन भी प्रयुक्त किया जाता हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में सड़कों की लम्बाई सर्वाधिक हैं जो की इसके औधोगिक विकास का प्रमुख सहायक हैं विश्लेषण से यह बताया जा सकता हैं कि जिन प्रदेशों का सड़क घनत्व अधिक हैं वहाँ का औधोगिक विकास भी अधिक हैं। लेकिन पूर्वी मैदान का सड़क घनत्व अधिक हैं तथा सभी प्रकार के परिवहन साधनों के विकास के और व्यापक संभावना के बावजूद औधोगिक रूप से पिछड़ा हुआ हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि परिवहन के साधन उद्योगों के स्थानीयकरण में सहायक हैं किन्तु यह एकमात्र कारक नहीं हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश दुर्गम होने के बावजूद भी सड़क एवं रेल परिवहन के विकास के पीछे कच्चे माल एवं उद्योगों की संभावना हैं। दिल्ली मुंबई औधोगिक गलियारे का विकास आरावली पर्वत के सहारे सहारे किया गया हैं , जिससे इस क्षेत्र में और औधोगिक विकास की संभावना बढ़ गयी हैं।

2. उर्जा

विद्युत उर्जा की खोज एवं प्रसार से पूर्व उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक था क्योंकी तब तक उर्जा के सिमित साधन (लकड़ी, कोयला एवं पेट्रोलियम) एवं स्थानाबद्ध थे। वर्तमान में विद्युत उर्जा के रूप में विद्युत उर्जा का उत्पादन सौर उर्जा, जल, पवन, बायोमास, भू–ताप, समुद्री ज्वार आदि से किया जा रहा हैं। साथ ही उर्जा का संग्रहण एवं वितरण आसन होने से उद्योगों के स्थानीयकरण में इसका प्रभाव कम हो गया हैं।

3. पूंजी एवं श्रम

पूंजी एवं श्रम का पलायन उन क्षेत्रों में किया जा सकता हैं जहाँ उद्योगों की स्थापना की जानी हैं। उद्योगीकरण एवं नगरीकरण एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं अतः यह हमेशा सत्य नहीं हो सकता कि उद्योगों की स्थापना नगरीय क्षेत्रों में इसलिये कि जाए की वहाँ श्रमिकों का जमाव रहता हैं। किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न औधोगिक गतिविधियों के बढ़ने पर भी श्रमिकों की उपलब्धता में वृद्धि हो सकती हैं तथा यह भी संभव हैं कि औधोगिक रूप से विकसित किसी नगरीय क्षेत्र में विशिष्ट कौशल के श्रमिको का अभाव हो। जैसे की सूचना तकनीक से संबंधित उच्च कौशल आधारित श्रमिक सभी जगह उपलब्ध नहीं होते है बल्कि इनकी जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ ये पलायन करते हैं। 2000 के दशक के मध्य में किए गए अध्ययनों के अनुसार, हम कह सकते हैं कि – (1) तकनीकी परिवर्तन और अधिक कुशल परिवहन ने कच्चे माल तक पहुंच के महत्व को कम कर दिया है, (2) संघीकरण, शिक्षा की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता और व्यावसायिक माहौल अधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं और (3) करों और अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का औद्योगिक स्थान की पसंद पर बहुत कम प्रभाव पड़ता हैं (बद्री, 2007, डीचमैन और अन्य, 2005, लाल और चक्रवर्ती, 2003)।

4. समूहीकरण

मिरडाल (1958) ने संचयी कारण की अवधारणा का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि विकास उन क्षेत्रों में केंद्रित क्यों हो जाता है, जहां इसे शुरू किया गया है। एक बार जब क्षेत्र बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सभी गतिविधियां वहां केंद्रित होने लगती हैं, क्योंकि सभी आंतरिक और बाहरी अर्थव्यवस्थाओं का आनंद लेना चाहते है, जो विकास के संचयी लाभ हैं। इस प्रकार, ''इस प्रक्रिया कारण के कारण, एक सामाजिक प्रक्रिया संचयी हो जाती है और अक्सर एक साथ एक त्वरित दर से गति बढ़ने लगती है''।

समूहीकरण के परिणामस्वरूप अनुसंधान और कुशल श्रम हस्तांतरण के माध्यम से ज्ञान और तकनीकी योग्यता का आदान–प्रदान भी होता है। इसलिए, उद्योग उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां ज्ञान और कुशल श्रम का ऐसा ढेर पहले ही हो चुका है ताकि वे इस तरह के आसानी से उपलब्ध तकनीकी ज्ञान को अपना सकें और आसानी से उपलब्ध कुशल श्रम का उपयोग कर सकें (रोड्रिक, 2004)। कुशल श्रमिकों का प्रवास भी अंततः इन क्षेत्रों में निर्देशित हो जाता है और यह चक्रीय हो जाता है। उद्योगों का स्थानीयकरण शायद क्षेत्र–विशिष्ट लाभों के कारण सख्ती से हो सकता है, इस मामले में परिधान उद्योगों, सॉफ्टवेयर उद्योगों, ऑटोमोबाइल उद्योगों आदि के क्लस्टर हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, हम ज्ञान अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित आईटी हब के गठन में इस पैटर्न को देखते हैं।

ज्ञान आधारित उद्योगों की स्थापना किसी भी नगरीय केंद्र में की जा सकती हैं क्योंकि इसमें विशिष्ट कुशलता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती हैं। तकनीक, ज्ञान एवं शोध और विकास (R&D) आधारित उद्योगों का विकास उन क्षेत्रों में किया गया हैं जहाँ व्यापक नगरीय सुविधाए उपलब्ध हैं। जबकि इन उद्योगों में समूहीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश के अलवर, जयपुर एवं अजमेर जिलों में, हाड़ौती प्रदेश में कोटा शहर, शुष्क प्रदेश में जोधपुर एवं बाड़मेर में समूहीकरण का प्रभाव देखने को मिलता हैं। राजस्थान में औधोगिक विकास की विषमता का एक प्रमुख कारण समूहीकरण भी हैं, इसी का प्रभाव हैं कि राजस्थान की अधिकांस औद्योगिक इकाइयाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश एवं इसके आस–पास अवस्थित हैं।

5. अवसंरचना

औधोगिक विकास, उद्योगों के सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी निर्भर करता हैं। इसमें औद्योगिक भूमि, बैंकिंग एवं वित्त सुविधायें, कैप्टिव पावर प्लांट, जलापूर्ति, सड़कें, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और अपशिष्ट उपचार शामिल हैं। ऐसा देखा गया हैं कि जिन जिलों में रिको द्वारा 'औधोगिक क्षेत्रों' का विकास किया गया हैं वहाँ औधोगिक विकास अधिक हुआ हैं क्योंकी इन क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास हुआ है, जिनमे भूमि का पट्टा, पानी एवं बिजली कनेक्शन, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और अपशिष्ट उपचार, भण्डारण, परिवहन सुविधाए आदि के साथ निर्यात सुविधायें, पर्यावरणीय छूट, प्रमाणीकरण, समाशोधन आदि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।

सारणी 6 : रीक्को क्षेत्र

RIICO DISTRICT REPORT 2018-19				
Region	No.of Industrial (I.A.)	Total area (Land Acquired) (in acres)	Total area developed (in acres)	No. of Plots alloted
ARAVALI	154	38156.84	28959.45	27493
EASTERN PLAIN	32	4751.22	2746.1	3615
HADAUTI PLATEAU	39	5224.81	3925.84	4704
SEMI ARID	68	10756.96	7277.32	10562
ARID	14	1221.72	1089.89	1366

Source : RIICO

चार्ट 4 :

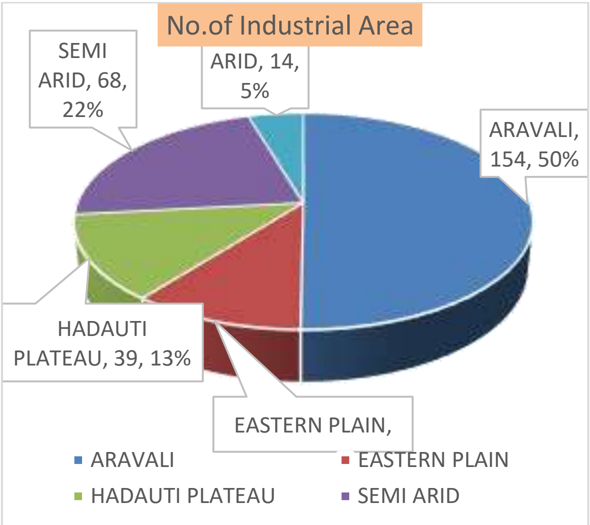

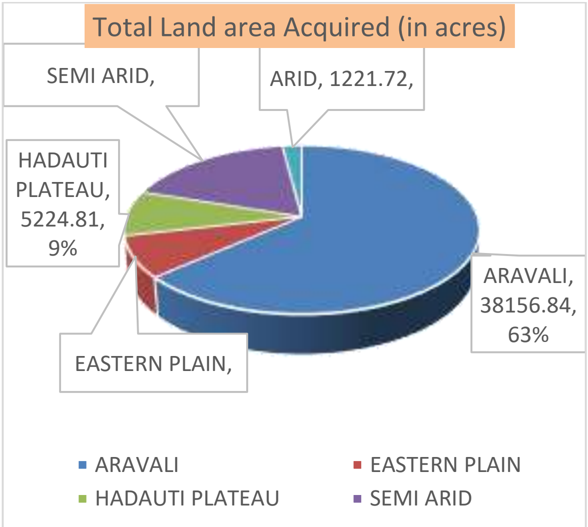

वर्तमान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विभिन्न प्रकार के पार्कों जैसे जापानी पार्क, कोरियाई पार्क फूड पार्क, स्पाइस पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क, सॉफ्टवेयर पार्कों की स्थापना की गई हैं जिनमे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस प्रकार के सर्वाधिक अवसंरचनाएं अरावली पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक हैं। एस ई जेड अधिनियम, 2005 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं : (1) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन (2) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देनाय (3) घरेलू और विदेशी स्त्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना (4) रोजगार के अवसरों का सृजन और (5) अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।

6. राजनितिक कारक

राजनितिक इच्छाशक्ति क्षेत्र विशेष में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक औद्योगिक विकास का कारण बनता हैं। प्रभावशाली नेता और मंत्री, संतुलित औद्योगिक विकास को दरकिनार करते हुए, अपने क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हैं, ताकि भविष्य में चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार की मानसिकता अंततः प्रादेशिक औद्योगिक विषमता को जन्म देती हैं। जोधपुर, जयपुर एवं उदयपुर इस प्रकार के औद्योगिक विकास के प्रमुख उदाहरण हैं।

7. ऐतिहासिक कारक

स्वतंत्रता के पूर्व थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास रियासतों के राजधानी नगरों में था क्योंकि उनके उद्योगों का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय रियासत एवं रियासती जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इन्हीं राजधानी नगरों के केन्द्रों में स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,

कोटा आदि नगर इसके अच्छे उदहारण हैं तथा कालांतर में इन नगरों को केंद्र में रखकर औधोगिक विकास की योजनाओं का निर्माण किया गया जिससे अंततः राजस्थान में प्रादेशिक औधोगिक विषमता को बढ़ावा मिला।

8. अन्य कारक

बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा निवेश क्षेत्रीय रूप से केंद्रित थे क्योंकि बड़े व्यापारिक घराने ''संतुलित क्षेत्रीय औद्योगीकरण'' में रुचि नहीं रखते हैं बल्कि अपने लाभ को प्राथमिकता देते हैं (बनर्जी और घोष 1988) ।
सामाजिक संस्थाएं, समाज के सांस्कृतिक मानदंड एक ऐसा कारक है जो अन्य औपचारिक संस्थानों की तुलना में कम दिखाई देता हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे मानदंड कार्यस्थलों में महिलाओं की भागीदारी या उनके द्वारा पूरी की जाने वाली शिक्षा के स्तर, अपंजीकृत उद्योगों के निरंतर अस्तित्व, कारखाने के काम के लिए बाल श्रम का उपयोग आदि निर्धारित करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे नकारत्मक कारक सस्ते श्रम को उपलब्ध करवाते हैं, जो कि उद्योगों के स्थानीयकरण का एक कारक हैं।
राखी भट्टाचार्य (2015), का कहना है कि आर्थिक भौगोलिक अध्ययन को शामिल किए बिना केवल शास्त्रीय औद्योगिक अर्थशास्त्र निर्णायक नहीं हो सकता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय चरित्र और संरचना को शामिल किया गया हैं। अतः उद्योगों की स्थापना में न केवल आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए बल्कि भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखकर प्रादेशिक औधोगिक विषमता को कम किया जा सकता हैं।

निष्कर्ष

राजस्थान का भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर औधोगिकीकरण का विश्लेषण करने पर पाया गया कि सभी प्रदेशों में औधोगिकीकरण का स्तर भिन्न भिन्न है, जिनके कारण भी अलग है। रजस्थान में किसी प्रदेश के औधोगिक विकास को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों में खनिज सम्पदा, परिवहन तंत्र तथा बाजार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में औधोगिक विकास के पीछे राजनितिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में खनिजों की बहुलता होने के कारण उधोगों का सर्वाधिक विकास हुआ हैं, वहीँ पूर्वी मैदान एवं हाडौती के पठार में औधोगिक विकास के पीछे बाजार, श्रम एवं परिवहन की उपलब्धता है। स्थान का चुनाव फर्मों की रणनीतियों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वे योग्य श्रम, एक संभावित बाजार, लेकिन बुनियादी ढांचे, अच्छी पहुंच आदि की तलाश करते हैं: एक ''इष्टतम'' स्थान। दरअसल, स्थान अधिक या कम संख्या में कारकों से प्रभावित होता है। राजस्थान का औधोगिक विकास काफी हद तक खनिजों की उपलब्धता के अलावा ऐतिहासिक एवं राजनितिक कारकों से प्रभावित रहा है।

REFRENCES :-

1. Banerjee, Debdas and Anjan Ghosh (1988), 'Indian Planning and Regional Disparity in Growth', in Amiya Kumar Bagchi (ed.), Economy, Society and Polity: Essays in the Political Economy of Indian Planning, pp. 104–65. Calcutta: Oxford University Press.
2. Bhattacharya, Rakhee (2015), Regional Development and Public Policy Challenges in India, Springer.
3. Chakravarty, Sanjoy. (2003), "Industrial Location in Post-reform India: Patterns of Inter-regional Divergence and Intra-regional Convergence", Journal of DevelopmentStudies, Vol. 40, No. 2, pp. 120-52.
4. Deichmann, Uwe., S. V. Lall, S. J. Redding, and Anthony J. Venables (2008), "Industrial Location in Developing Countries", The World Bank Research Observer, Vol. 23, No. 2, pp 219-46.
5. Hewitt, T., H.Johnson & D. Wield 1992. Industrialization and development. Oxford: Oxford University Press. pp 1-6.
6. Joshi, H. (2008). Human Development Index Rajasthan. Institute of Development Studies, Jaipur, Concept Publishing Company,
7. Khosla, R., & Sharma, M. (2012). Regional Disparities in Industrial Development in India. Romanian Journal of Regional Science, 6(2).
8. Lall, S. V. and S. Chakravorty (2005), "Industrial Location and Spatial Inequality: Theory and Evidence from India", Review of Development Economics, Vol.9, No. 1, pp. 47–68.

9. Myrdal, Gunnar (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: GeraldDuckworth and Co.
10. North, D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance Cambridge: Cambridge University Press.
11. Sava, A. M. (2016). Weighting Method for Developing Composite Indices: Application for Measuring Sectoral Specialization. Journal of Applied Quantitative Methods, 2(3), 77–84.
12. Sharma, P. K. (2016). Disparities in Socio Economic Development in Thar Desert. International Journal of Research in Geography (IJRG), 2(3), 1–10. https://doi.org/10.20431/2454-8685.0203001
13. Sharma, P.K., Mishra P. & Verma, R.K. (2019-20) regional disparity in agricultural development in Bundelkhand region of Madhya Pradesh india. annals of RGA, 36, 68-78.
14. Singh, R.L. (2006). Regional Disparities in level of socio-economic development in Post Reforms period: A District level analysis, Annals of NAGI, 26(2), 509.
15. Statistical Abstract Application Of Rajasthan (SAAR), (2020). Statistical Abstract Application Of Rajasthan (SAAR). Retrieved 2022, from https://saar.raj.nic.in/departmentlist.aspx
16. Statistical Handbook. (2020) Directorate of Economic and Statistics, Govt of Rajasthan, Jaipur.
17. Webber, M. J. (1985), "Industrial location", Vol. 3, Sage Publication, New Delhi.